

जनजाति क्षेत्र में शैक्षिक पर्यवेक्षण सम्बन्धित चुनौतियाँ (बांसवाड़ा जिले के संदर्भ में एक अध्ययन)

डॉ. हरीश कुमार मेनारिया* मनीषा आमेटा**

* सहायक आचार्य (शिक्षा) लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, डबोक, उदयपुर (राज.) भारत

** शोधार्थी (शिक्षा) लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, डबोक, उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – प्रस्तुत शोध पत्र बांसवाड़ा जिले के संदर्भ में विद्यालयों में शैक्षिक पर्यवेक्षण से सम्बन्धित चुनौतियों पर आधारित है। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान संभावनाओं से भरा प्रदेश है भौगोलिक चुनौतियों एवं विविधताओं के बावजूद भी विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुआ है। आने वाला समय शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित ही राजस्थान के विद्यार्थियों का है एक समय था जब राजस्थान की गिनती शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में हुआ करती थी, लेकिन विगत कुछ सालों से राजस्थान ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में अपने कदम मजबूती से आगे बढ़ाए हैं। जनजाति क्षेत्र के चयनित जिलों में शैक्षिक पर्यवेक्षण संबंधी समस्याओं एवं चुनौतियों के अध्ययन के अन्तर्गत बांसवाड़ा जिले को अध्ययन में सम्मिलित कर शिक्षकों के जो अभिमत प्राप्त हुए उन्हें मूल्यमुक्त रूप से प्रदर्शित किया गया है।

शोध उद्देश्य :

1. जनजातीय जिले बांसवाड़ा में शैक्षिक पर्यवेक्षण सम्बन्धी चुनौतियों का अध्ययन करना।
2. जनजातीय जिले बांसवाड़ा में शैक्षिक पर्यवेक्षण सम्बन्धी चुनौतियों के समाधान पर सुझाव देना।

शोध विधि एवं अध्ययन क्षेत्र– अध्ययन का उद्देश्य राजस्थान राज्य के शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शैक्षिक पर्यवेक्षण सम्बन्धित प्रक्रिया व समस्याओं का अध्ययन करना है जो कि वर्तमान समय की समस्याओं से सम्बन्धित अध्ययन है अतः शोध विषय की प्रकृति एवं उद्देश्यों को ध्यान रखते हुए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के शहरी व ग्रामीण माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक सीमित रखा गया है।

बांसवाड़ा जिले का कुल क्षेत्रफल 5037 वर्ग किलोमीटर है जिसमें नगरीय क्षेत्रफल 22 वर्ग किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्रफल 5015 वर्ग किलोमीटर है। बांसवाड़ा की नींव महारावल जगमाल सिंह ने डाली थी। इस क्षेत्र में बांस के पेड़ प्रचुरता में पाए जाने व बांसिया भील द्वारा बसाये जाने के कारण इस क्षेत्र का नाम बांसवाड़ा पड़ा है। बांसवाड़ा के लगभग मध्य में से कर्क रेखा गुजरती है, जिस कारण इसका अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा दोनों को संयुक्त रूप से प्राचीनकाल में वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में यह प्रदेश वाग्वर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। इसकी राजधानी अर्धुना थी एवं इस

पर परमारों का शासन था। यह जिला एक जनजाति बहुल जिला है। राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 को बांसवाड़ा रियासत का राजस्थान में विलय हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार बांसवाड़ा जिले की जनसंख्या 17,97,485 है और लिंगानुपात 980, साक्षरता दर 56.3 प्रतिशत, पुरुष साक्षरता 69.5 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 43.1 प्रतिशत है।

न्यादर्श – अध्ययन हेतु दक्षिणी राजस्थान के जनजातीय धनत्व वाले बांसवाड़ा जिले से 20 विद्यालयों का चयन किया गया है। चयनित 20 विद्यालयों में से 5 शहरी क्षेत्र व 15 ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं तथा प्रत्येक विद्यालय से 5-5 शिक्षकों (कुल 100) का चयन न्यादर्श के रूप में किया गया।

शोध उपकरण – प्रस्तुत शोधकार्य में तथ्य संकलन हेतु उपकरण के रूप में शैक्षिक पर्यवेक्षण से सम्बन्धित चुनौतियों हेतु स्वनिर्मित अभिमत आवली को सम्मिलित किया गया है। जिसमें कुल 5 प्रश्नों को समाहित किया गया है जो निम्नानुसार हैं:-

1. क्या शैक्षिक पर्यवेक्षण जनजाति समूह के विद्यार्थियों के विकास में सहायक नहीं हो पाता है?
2. क्या शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रक्रिया में शाला प्रधान को शिक्षकों का सहयोग नहीं मिल पाता है?
3. क्या जनजाति क्षेत्र को भौगोलिक स्थिति के कारण पर्यवेक्षण सुचारु रूप से नहीं हो पाता है?
4. क्या संस्था प्रधान पर अतिरिक्त विभागीय जिम्मेदारियों के कारण पर्यवेक्षण प्रक्रिया बाधित होती है?
5. क्या विद्यालय में पर्यवेक्षण अधिकारियों से संबंधित असहजता बनी रहती है?

शिक्षकों के अभिमत

तालिका संख्या 0.1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

तालिका 0.1 में बांसवाड़ा जिले के उत्तरदाताओं से शैक्षिक पर्यवेक्षण का जनजाति समूह के विद्यार्थियों के विकास में सहायक नहीं होने पर प्रश्न किया गया जिसके जवाब में पाया गया कि शहरी क्षेत्र के 26.32 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र के 64.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हाँ में जवाब दिया है और शहरी क्षेत्र के 36.84 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र के 33.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपनी असहमती दी है। अतः तालिका में Chi² का मान 22.366 रहा जिसके आधार पर शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों के अभिमत

में 0.01 स्तर पर सार्थक अन्तर पाया गया।

तालिका संख्या 0.2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

तालिका 0.2 में बाँसवाड़ा जिले के उत्तरदाताओं से शाला प्रधान को शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रक्रिया में शिक्षकों का सहयोग नहीं मिलने पर प्रश्न किया गया जिसके जवाब में पाया गया कि शहरी क्षेत्र के 21.05 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र के 38.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हाँ में जवाब दिया है एवं शहरी क्षेत्र के 73.68 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र के 53.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नहीं में जवाब दिया है। अतः तालिका में χ^2 का मान 1.691 रहा जिसके आधार पर शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों के अभिमत में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया था।

तालिका संख्या 0.3 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

तालिका 0.3 में बाँसवाड़ा जिले के उत्तरदाताओं से भौगोलिक स्थिति के कारण जनजाति क्षेत्र में पर्यवेक्षण के सुचारु रूप से नहीं होने पर प्रश्न किया गया जिसके जवाब में पाया गया कि शहरी क्षेत्र के 31.58 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र के 34.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हाँ में जवाब दिया है। अतः प्राप्त तथ्यों के अनुसार χ^2 का मान 0.565 रहा इसके अनुसार शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों के अभिमत में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

तालिका संख्या 0.4 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

तालिका 0.4 में बाँसवाड़ा जिले के उत्तरदाताओं से संस्था प्रधान पर अतिरिक्त विभागीय जिम्मेदारियों के कारण पर्यवेक्षण प्रक्रिया बाधित होने पर प्रश्न किया गया जिसके जवाब में पाया गया कि शहरी क्षेत्र के 73.68 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र के 66.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हाँ में जवाब दिया है। अतः तालिका में χ^2 का मान 0.097 रहा एवं शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों के अभिमत में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

तालिका संख्या 0.5 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

तालिका 0.5 में बाँसवाड़ा जिले के उत्तरदाताओं से विद्यालय में पर्यवेक्षण अधिकारियों से संबंधित असहजता बने रहने पर प्रश्न किया गया जिसके जवाब में पाया गया कि शहरी क्षेत्र के 36.84 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र के 42.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हाँ में जवाब दिया है। अतः प्राप्त तथ्यों के अनुसार तालिका में χ^2 का मान 1.148 रहा इसके अनुसार शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों के अभिमत में कोई अन्तर नहीं पाया गया।

निष्कर्ष :

1. शहरी क्षेत्र के 26.32 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र के 64.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने शैक्षिक पर्यवेक्षण को जनजाति समूह के विद्यार्थियों के विकास में सहायक नहीं माना है।
2. शहरी क्षेत्र के 73.68 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र के 53.33 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि शाला प्रधान को शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रक्रिया में शिक्षकों का सहयोग नहीं मिलता।
3. शहरी क्षेत्र के 31.58 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र के 34.67 प्रतिशत

उत्तरदाताओं के अनुसार भौगोलिक स्थिति के कारण जनजाति क्षेत्र में पर्यवेक्षण के सुचारु रूप से नहीं हो पाता है।

4. शहरी क्षेत्र के 73.68 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र के 66.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार संस्था प्रधान पर अतिरिक्त विभागीय जिम्मेदारियों के कारण पर्यवेक्षण प्रक्रिया बाधित होती है।
5. शहरी क्षेत्र के 36.84 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र के 42.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार विद्यालय में पर्यवेक्षण अधिकारियों से संबंधित असहजता बनी रहती है जिससे पर्यवेक्षण प्रक्रिया बाधित होती है।

सुझाव:

1. पर्यवेक्षण कार्य समन्वित एवं सुनियोजित तरीके से विकास के लिए समग्र नीतियों का समन्वयन द्वारा किया जावे।
2. नयी-नयी योजनाओं और आवश्यक नियमों का नियोजन होना चाहिए एवं परिवर्तन द्वारा नए नियमों का निर्माण एवं नवाचार को बढ़ावा दिया जाए।
3. शिक्षकों को गैर शैक्षिक गतिविधि में नहीं लगाना चाहिए एवं विद्यार्थी को भयमुक्त रखने का प्रयास करते हुए वातावरण मित्रतावत एवं उचित सहयोग देने वाला होना चाहिए।
4. पर्यवेक्षणकर्ता सम्बलन प्रदाता के रूप में हो एवं समय-समय पर पर्यवेक्षण कर सही समाधान करने वाला होना चाहिए।
5. पर्यवेक्षण के सुझाव लिखित रूप में देने चाहिए एवं छात्रों द्वारा बोली जाने वाली स्थानीय बोली में चर्चा का आयोजन किया जाए। पर्यवेक्षणकर्ता सहज रूप से चर्चा करें।
6. विद्यालय में पर्यवेक्षण औपचारिक मात्र नहीं होना चाहिए। पर्यवेक्षण के दौरान जो कमियाँ हैं उन्हें दूर करने हेतु कार्य योजना बनाकर दुबारा देखना चाहिए।
7. सुधारात्मक कार्यों पर बल, भौतिक, शैक्षिक व मानवीय संसाधनों की कमी को पूरा करने का प्रयास किया जाए।
8. जनजाति क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए समय-समय पर निर्देशन एवं प्रशिक्षकों द्वारा सेमिनार का आयोजन किया जाए तथा विद्यालय में खेलकूद की गतिविधियों के नियमित संचालन एवं सहभागिता को बढ़ावा दिया जाय।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. McFee, J. (2017). City Maps Banswara India. (n.p.): CreateSpace Independent Publishing Platform.
2. Rajasthan District G.K.: English Medium. (n.d.). (n.p.): Atharv Publication.
3. प्रो. एल. के. ओड़, (2014) 'शैक्षिक प्रशासन', राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी।
4. सुरेन्द्र कुमार साहरण, (2008) 'शैक्षिक पर्यवेक्षण का स्वरूप एवं प्रासंगिकता', शिविरा पत्रिका।

तालिका संख्या 0.1 : शैक्षिक पर्यवेक्षण और विद्यार्थियों का विकास

अभिमत	शहरीN= 19	प्रतिशत	ग्रामीणN=75	प्रतिशत	कुलN=94	कुल प्रतिशत	Chi ² Sq.	Sig.
हाँ	5	26.32	48	64.00	53	56.38	22.366	0.01
नहीं	7	36.84	25	33.33	32	34.04		
अनिश्चित	7	36.84	2	2.67	9	9.57		
कुल योग	19	100.00	75	100.00	94	100.00		

तालिका संख्या 0.2 : शाला प्रधान को शिक्षकों का सहयोग नहीं मिलता है

अभिमत	शहरीN= 19	प्रतिशत	ग्रामीणN=75	प्रतिशत	कुलN=94	कुल प्रतिशत	Chi ² Sq.	Sig.
हाँ	4	21.05%	29	38.67%	33	35.11%	1.691	असार्थक
नहीं	14	73.68%	40	53.33%	54	57.45%		
अनिश्चित	1	5.26%	6	8.00%	7	7.45%		
कुल योग	19	100.00%	75	100.00%	94	100.00%		

तालिका संख्या 0.3 : भौगोलिक स्थिति और पर्यवेक्षण

अभिमत	शहरीN= 19	प्रतिशत	ग्रामीणN=75	प्रतिशत	कुलN=94	कुल प्रतिशत	Chi ² Sq.	Sig.
हाँ	6	31.58	26	34.67	32	34.04	0.565	असार्थक
नहीं	11	57.89	37	49.33	48	51.06		
अनिश्चित	2	10.53	12	16.00	14	14.89		
कुल योग	19	100.00	75	100.00	94	100.00		

तालिका संख्या 0.4 : संस्था प्रधान एवं अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ

अभिमत	शहरीN= 19	प्रतिशत	ग्रामीणN=75	प्रतिशत	कुलN=94	कुल प्रतिशत	Chi ² Sq.	Sig.
हाँ	14	73.68	50	66.67	64	68.09	0.097	असार्थक
नहीं	5	26.32	25	33.33	30	31.91		
अनिश्चित	0	0.00	0	0.00	0	0.00		

तालिका संख्या 0.5 : पर्यवेक्षण अधिकारियों से सम्बन्धित असहजता

अभिमत	शहरीN= 19	प्रतिशत	ग्रामीणN=75	प्रतिशत	कुलN=94	कुल प्रतिशत	Chi ² Sq.	Sig.
हाँ	7	36.84%	32	42.67%	39	41.49%	1.148	असार्थक
नहीं	12	63.16%	40	53.33%	52	55.32%		
अनिश्चित	0	0.00%	3	4.00%	3	3.19%		
कुल योग	19	100.00%	75	100.00%	94	100.00%		
